राष्ट्र हित में शिक्षा | शिक्षा हित में शिक्षक | शिक्षक हित में समाज

पंजीयन क्रमांक-72/54-55

फोन : 0141-2377799, 2362212

E-mail : rss.rashtriya@gmail.com

Website : www.rssrasthriya.org

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001

संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा

प्रदेश महासमिति अधिवेशन

12–13 दिसम्बर 2020

स्थान : सी.एल.सी. परिसर, पिपराली रोड़, सीकर

महामंत्री प्रतिवेदन

सम्पत सिंह	देवलाल गोचर	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री

संपूर्ण राजस्थान से प्रदेश महासमिति अधिवेशन में पधारें संगठन के जुझारू, संघर्षशील एवं कर्मयोगी शिक्षक बन्धुओं एवं मातृस्वरूपा बहिनों।

सादर वन्दे!

संगठन के प्रदेश महासमिति अधिवेशन के इस गौरवशाली अवसर पर कोविड–19 की महामारी से संघर्ष व बचाव कर अपने अमूल्य समय का योगदान प्रदान करने बाबत् इस शेखावाटी की भूमि सी.एल.सी. परिसर, पिपराली रोड़ सीकर में उपस्थित समस्त प्रदेश महासमिति सदस्य महानुभावों का हार्दिक वन्दन व अभिनन्दन करते हुए प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन बीकानेर में सम्पन्न होने के बाद क्रमशः संगठनात्मक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

बन्धुओं! वैश्विक महामारी कोविड–19 ने सम्पूर्ण विश्व में कैसा ताण्डव किया?आज समूचे भारत देश में कोरोना ने पाँव पसार कर आप व हम सभी के घर आँगन के बाहर हम सब को झकझोर दिया है, मनः विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सभी ने त्याग, समर्पण व अमूल्य समय प्रदत्त कर संवेदनशीलता पूर्वक राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर राज्य सरकार से परोक्ष व अपरोक्ष रूप से आन्दोलन के विभिन्न चरण अपना कर सामाजिक सरोकार व रचनात्मक कार्य करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर **'शिक्षक, शिक्षा व शिक्षार्थी'** के हितार्थ संघर्ष की राह अपनाकर प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इस अवसर पर विगत माह में जो राजस्थान सरकार से उसकी मनमानी, तानाशाहीपूर्ण व कर्मचारी विरोधी नीतियों के दमन व कुत्सित प्रयासों को नाकाम कर सरकार को अपने ही आदेशों को वापस शिक्षकों के हितार्थ लेने पर मजबूर किया है ये सब आपकी कर्तव्य व ध्येयनिष्ठा का सकारात्मक परिणाम हैं। संगठन के प्रयास व उपलब्धियाँ मुख्यतयाः एक दृष्टि में :–

दिनांक 18 जनवरी 2020 को राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को जुलाई 2019 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कराने बाबत्

काढ़ा वितरण करते संगठन के कार्यकर्त्ता

संगठन के कार्यकर्त्ता द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान

राज्य के समस्त जिलाध्यक्ष महानुभावों द्वारा जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से अविलम्ब घोषणा व भुगतान कराने बाबत् ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित कराये गए। उस दिशा में संगठन का प्रयास आज तक जारी हैं।

दिनांक 21 मार्च 2020 को माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव–स्कूल शिक्षा तथा निदेशक–मा.शि. महोदय को वैश्विक महा आपदा कोविड–19 के कोराना वायरस प्रकोप के कारण विद्यालयों में शिक्षकों को कार्यस्थल पर उपस्थिति से मुक्त करवाने बाबत् संगठन ने राज्य सरकार से पुरजोर ढंग से माँग की, जिस पर सरकार ने तत्काल कार्यवाही कर शिक्षकों को राहत प्रदान की।

कोविड–19 से निपटने, निर्धनों तथा जरूरतमंदों को सहायता व राहत पहुँचाने हेतु शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने बाबत् संगठन की अपील पर दिनांक 23 मार्च 2020 को संगठन ने सर्वप्रथम स्वेच्छा से पहल कर इस मुहिम में बढ़–चढ़कर भाग लेते हुए राजकोष में यथाशक्ति राशि जमा करा महामारी की संवेदनशीलता को अनुभव किया। यह हम सब की राष्ट्रभक्ति का एक संदेश है।

दिनांक 26 अप्रैल 2020 को संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव एवं सचिव–स्कूल शिक्षा को शिक्षकों को अप्रैल 2020 माह से पूर्व वेतन भुगतान कराने का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिस पर राज्य सरकार ने पूर्ण भुगतान के आदेश जारी कर राहत पहुँचाई।

दिनांक 16 मई 2020 को संगठन द्वारा माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री को संस्कृत शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों की पदौन्नति शीघ्र कराने हेतु ज्ञापन प्रेषित करा ध्यान आकर्षण कराया, जिस पर विभाग द्वारा आदेश क्रियान्वित करा पदौन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

साथ ही कोविड–19 की ड्यूटी से मानसिक तनाव से ग्रस्त सिरोही के शिक्षक भीमाराम की आत्महत्या प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों को सजा देने की भी माँग की गई

मै इस अवसर पर विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि राज्य कर्मचारियों में पुलिस व चिकित्सकाकर्मियों को छोड़कर समूचे शिक्षक समुदाय व अन्य विभागों के कर्मचारियों से उनकी बिना सहमति के ही प्रतिमाह वेतन कटौती के मनमाने व तानाशाही भरे आदेश जारी कर दिये जिसका राज्य की समस्त उपशाखाओं द्वारा दिनांक 07.09.2020 को उपखण्ड अधिकारी महानुभावों के माध्यम से राज्य सरकार को वेतन कटौती नहीं कराने, उपार्जित अवकाश के नगद भुगतान पर रोक हटाने व मार्च 2020 का स्थगित वेतन दिलाने बाबत् मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री तथा मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। ठीक इसी क्रम में दिनांक 8 से 15 सितम्बर 2020 तक उक्त सन्दर्भ के ई–मेल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संगठन के सदस्यों द्वारा प्रेषित किए गए। दिनांक 10 सितम्बर 2020 को राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त आदेश को स्थगित नहीं करने के एवज में राज्य के शिक्षक समुदाय व संगठन के माननीय सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा काली पट्टी व काले मास्क लगाकर राज्य सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरूद्ध आन्दोलन किया गया। यहीं नहीं इस वेतन कटौती के आदेश में आक्रोशित हो संगठन के पदाधिकारियों ने दिनांक 13.09.2020 को संभाग स्तर पर प्रेसवार्ता कर सरकार पर दबाव लाने का सकारात्मक प्रयास किया।

दिनांक 17.09.2020 को मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं सचिव–स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर राज्य के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की संगठन द्वारा माँग की गई। यहीं नहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न संवर्गों यथा प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों की मनमानी तरीके से प्रतिदिन उपस्थिति पंजिकाओं की छाया प्रतियाँ मँगवाने पर तत्काल रोक लगाने तथा ज्वलन्त समस्याओं के समाधान बाबत् संस्कृत शिक्षामंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं शासन सचिव–स्कूल शिक्षा व संस्कृत शिक्षा को दिनांक 23.09.2020 को पत्र संगठन द्वारा भिजवाया गया।

संघर्ष की कड़ी में वेतन कटौती के विषय में सरकार की संवेदनहीनता संगठन को प्रतीत होने पर दिनांक 25.09.2020 को जिला स्तर पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा वेतन कटौती नहीं करने तथा उपार्जित अवकाश के भुगतान से रोक हटाने बाबत् पुनः राज्य सरकार को ज्ञापन भिजवाये गए। लगातार सरकार द्वारा कठोर रवैया अपनाने पर संगठन ने दिनांक 26 सितम्बर 2020 से 05 अक्टूबर 2020 तक राज्य के शिक्षकों व संगठन के सदस्य महानुभावों द्वारा वेतन कटौती नहीं कराने बाबत् मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को पोस्ट–कार्ड लिखकर अभियान चलाया गया ताकि सरकार इस ज्वलन्त मुद्दे पर चिंतन कर शिक्षकों को राहत प्रदान करें।

मित्रों! लॉक–डाऊन अवधि के बाद जब राज्य ने विद्यार्थियों को घर पर ही रहने के आदेश प्रदान कर रखे थे, कुछ विद्यालय के गुरुजन व बहिने अपना–अपना दायित्व निर्वहन कर रही थी, फिर भी जोधपुर के संभागीय आयुक्त तत्कालीन डॉ. समित शर्मा ने जो महिला

शिक्षिकाओं के प्रति कठोरतापूर्ण अभद्र व्यवहार कर प्रताड़ित किया जिसका विडियो वायरल होकर समाचार पत्रों में भी शिक्षकों व विभाग की छवि धूमिल की। जिस पर संगठन ने नीतिगत निर्णय लें जोधपुर संभागीय आयुक्त के परिपत्र दिनांक 22.10.2020 के विरूद्ध 23.10.2020 को मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख सामन्तशाही प्रवृत्ति के प्रशासनिक अधिकारी को आदेश पर अंकुश व क्रियान्वयन पर दिनांक 27.10.2020 को रोक की माँग की गई। यहीं नहीं दिनांक 27.10.2020 को दीपावली से एक सप्ताह पहले राज्य कर्मचारियों के समान शिक्षकों को भी बोनस के आदेश जारी कराने की माँग की जिस पर राज्य सरकार ने आदेश जारी करा दीपावली पर उपहार प्रदान किया। 2.11.2020 को संगठन द्वारा निरन्तर शिक्षकों के हित में दीपावली अवकाश की घोषणा के साथ ही नवम्बर 2020 का शिविरा पंचांग जारी कराने की भी माँग का पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया जिस पर सरकार ने यथा समय संगठन की माँग को उचित मानते हुए आदेश जारी किए।

दिनांक 02.11.2020 को ही राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के तहत चरणबद्ध योजना से वेतन कटौती के लिए किए संघर्ष में सफलता नहीं मिलने पर संगठन द्वारा संघर्ष जारी रखते हुए राज्य के शिक्षक समुदाय के हितार्थ माननीय उच्च न्यायालय में उक्त संदर्भ के विरूद्ध याचिका लगा वेतन कटौती नहीं करवाने बाबत् गुहार की गई। जिस पर माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार के वेतन कटौती के निर्णय के आदेश से पूर्व ही सरकार ने संगठन के दबाव के कारण वेतन कटौती स्वेच्छिक करने के आदेश जारी किये।

साथ ही राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) द्वारा दिनांक 9.11.2020 को ही पंचायत राज, स्थानीय एवं शहरी निकाय चुनाव में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग को पत्र लिखकर अनियमितता दूर करने की माँग की गई जिस पर निर्वाचन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए संगठन को प्रत्युत आदेश जारी कर राहत प्रदान की। इधर संगठन ने आवागमन के साधन बन्द होने से लॉक–डाऊन अवधि में शिक्षकों को अपने मूल पदस्थापन पूर्व में स्थान से मूलनिवास गृह जिलों जाकर निवास करने से उत्पन्न नियमों में आई पेचीदगी को दूर कराते हुए जो शिक्षक जहाँ निवासरत है उसे वहीं पर या प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति मान ड्यूटी कराने के आदेश माननीय निदेशक महोदय, बीकानेर से जारी करा शिक्षक समुदाय जो हजारों की तादाद में थे उन्हें राहत प्रदान कराई।

संगठन के नीति निर्धारकों ने इस विषय पर गंभीरता से चिन्तन कर चिंता व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया कि जब विद्यार्थी विद्यालय पढ़ने आ ही नहीं रहे है तो वर्तमान में जो विद्यालय का समय 7:30 से 1:00 बजे का है वो ही यथावत् रखते हुए 10:00 बजे से 4:00 बजे तक का विद्यालय समय कोविड–19 के तहत अनुचित अनुभव किए जाने से माह अक्टूबर 2020 तक विद्यालय समय परिवर्तन नहीं कराने के बाबत् पत्र श्रीमान् मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री व मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित करा यथावत रखने की माँग की गई जिस पर राज्य सरकार ने संगठन के सोच व चिन्तन को शायद सही ठहराते हुए विद्यालयों के समय को यथावत् रखने के आदेश जारी किए।

बंधुओं! संगठन शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थियों के हितार्थ प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सदैव मानक व मानदण्डों पर खरे उतरने का आप सभी के सहयोग से सकारात्मक रूप से प्रयसारत रहा है एवं आगे भी समर्पित भाव से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हैं।

मैं इसी क्रम में आप सभी का एक बार फिर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जिन शिक्षक साथियों ने कोरोना महामारी कोविड–19 के संक्रमण का भय तथा माह मई व जून 2020 की भीषण गर्मी में अपने–अपने कर्तव्य स्थल पर प्रशासन द्वारा विभिन्न दायित्व निर्वहन करने के आदेशों की अनुपालना करने पर ग्रीष्मावकाश में कार्य करने की एवज में उपार्जित अवकाश **(PL)** देने के बाबत् ज्ञापन व पत्र लिखकर पुरजोर ढंग से माँग की गई। राज्य सरकार ने शिक्षकों से मूल कर्तव्य के सिवाय गैर शैक्षणिक कार्य करने हेतु शिक्षकों को कई दायित्व प्रदान कर रखे है जिन्हें आप भली–भाँति अनुभव किया है फिर भी सरकार द्वारा बूथ लेवल के हमारे शिक्षक साथियों को "वन नेशन वन राशन कार्ड" के अन्तर्गत आधार सीडिंग एवं सत्यापन कार्य का दायित्व प्रदान किए जाने से शिक्षक समुदाय को समाज में आत्म सम्मान व गरिमा के प्रतिकूल अनुभव होकर आक्रोशित होना तथा संगठन को भी सरकार के इस आदेश के प्रति स्वाभाविक आक्रोश होने से लिए गए नीतिगत निर्णय से राज्य सरकार को ज्ञापन व पत्र भेजकर बूथ लेवल ऑफिसर के दायित्व निर्वहन कर रहे शिक्षकों के सम्मान में यह "वन नेशन वन राशन कार्ड" का कार्य किसी दूसरी एजेन्सी को दिलाने की माँग की गई जिस पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक चिन्तन कर आदेश जारी कर संशोधन आदेश निकालते हुए **(BLO)** को इस दायित्व से मुक्त कर यथावत रखने के आदेश संगठन के प्रयास से संभव हुए।

मित्रों! राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) मात्र अपने हितों की रक्षा के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों में भी स्वेच्छा से नैतिक धर्म का निर्वाह करते हुए 'वयम् राष्ट्रे जाग्रयाम्' 'इदम् न मम्' के आदर्श को अंगीकार करते हुए राष्ट्र के उत्थान में अपनी

धरना प्रदर्शन करते संगठन के कार्यकर्त्ता

शिक्षक समस्याओं पर मानव संसाधन मंत्री से वार्ता

आहुतियां देता आया है, ठीक इसी क्रम में हाल ही में जारी हुई भारत देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर संगठन द्वारा राज्य के नो संभागों में वेबिनार बैठकें आयोजित की गई। जिसमें संगठन के शीर्षस्थ पदाधिकारियों, विद्वानों तथा शिक्षाविदों ने अपने अनुभवों के तहत व्यावहारिकता लिए नई शिक्षा नीति पर प्रबोधन प्रदान कर निहित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला तथा शिक्षकों व आमजन को नई शिक्षा नीति हेतु जन–जागरण अभियान हेतु प्रेरित कर शिक्षा नीति को जनोपयोगी बनाने हेतु रचनात्मक सुझाव भिजवायें। हरित राजस्थान के तहत "धरती माँ का करें श्रृंगार" के कार्यक्रम में हजारों पौधे लगाये जाकर पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। कोरोना लॉक–डाऊन अवधि में संगठन के सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण राज्य से लाखों सदस्यों ने स्वयं की धनराशि से प्रधानमंत्री राहत कोष एवं मुख्यमंत्री राहत कोष तथा स्थानीय राहत कोष में 1908108/– रूपये जमा करायें। साथ ही राशन किट, भोजन पैकेट, मास्क वितरण, काढा वितरण, गौशाला में चारा, परिण्डे बांधना तथा पक्षियों के दाना व रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

बन्धुओं! शिक्षकों की अनेक समस्याएँ जिन्हें संगठन के माँगपत्र में संकलित कर संगठन द्वारा सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। मैं इस अधिवेशन में संगठन के माध्यम से राज्य सरकार का पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए माँग करता हूँ कि शिक्षकों की छठें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए सातवे वेतनमान में पे–मैट्रिक्स व लेवल निर्धारित कर दिनांक 01.01.2016 से नकद लाभ देते हुए वेतन विसंगतियों का निराकरण करें। शिक्षकों से गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दिलाने, शेष योग्यताधारी पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षकों को प्रबोधकों के पद पर समायोजित करने तथा प्रबोधकों को शिक्षकों के समान समुचित पदौन्नति के अवसर प्रदान कर उन्हें वित्तीय लाभ दिलाने, जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते की नकद घोषणा कर उपार्जित अवकाश पर लगी रोक हटाने तथा उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने के आदेश जारी कराने, साथ ही मार्च 2020 के शेष भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर नगद भुगतान कराने की माँग आज भी ज्वलन्त समस्या बनी हुई है जिसके लिए संगठन शिक्षकों को न्याय दिलाने बाबत संघर्षरत रह संकल्पित हैं।

मैं इस अधिवेशन के अवसर पर अन्त में एक ज्वलन्त समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कर आपके सहयोग की कामना करता हूँ कि, राज्य सरकार ने हाल ही कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से स्माईल–2 कार्यक्रम का आगाज किया है। इस आदेश की क्रियान्विति होने पर राज्य का शिक्षक समुदाय कोरोना महामारी से भयग्रस्त होकर तनाव में हैं। गौरतलब है कि स्माईल–2 के तहत विद्यार्थियों से वाट्स–अप के माध्यम से गृहकार्य दिए जाने व वाट्स–अप पर ही गृहकार्य विद्यार्थियों द्वारा मंगवाकर प्रिंट निकलवाकर मूल्यांकन के बाद पोर्टफोलियो में लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जिन बालकों के पास एंड्रायड स्मार्ट फोन की सुविधा नहीं होने पर उनके घर जाकर गृहकार्य देने व पुनः घर–घर जाकर गृहकार्य को संकलित कर मूल्यांकन के आदेश जारी किए है जिसका पुरजोर विरोध करते हुए राज्य के अधिकांश जिलों में संगठन की इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित करा ज्ञापन प्रस्तुत कर सरकार को विरोध जताते हुए कोरोना संक्रमण के फैलने व शिक्षक की सुरक्षा की चिन्ताओं से अवगत कराया है। यहीं नहीं संगठन ने आक्रोश जताते हुए कहा कि एक तरफ राज्य व भारत सरकार कोविड–19 की गाईड–लाईन में नित्य प्रति संशोधन कर आमजन को जीवित रखने के लिए आदेश जारी कर पालना करा रही है वहीं दूसरी ओर राज्य के शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के अव्यावहारिक आदेशों के क्रियान्वयन से राज्य में तेजी से शिक्षकों व विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने से कोरोना के संक्रमण फैलने की आशंका बलवती हो रही है।

बंधुओं! संगठन की दृष्टि से यह अत्यन्त विकट समय है। इस समय सांगठनिक एकता और दृढ़ता ही हमारे लिए संजीवनी सिद्ध हो सकती है। हमें एकजुट होकर कोराना जैसी महामारी से बचाव करते हुए विभिन्न चुनौतियों का सकारात्मक प्रयास करते हुए हमें समाधान निकालना होगा। कोरोना संक्रमण काल में बनी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सरकार कोई भी विरोधी नीति के निर्णय ले सकती है अतः हमें अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान अहर्निश प्रतिबद्ध व संकल्पित रह जागरूक रहना होगा। साथ ही हमें बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए नित नई तकनीक व नवीन ज्ञान से रू–ब–रू होकर अद्यतन भी रहना होगा।

मित्रों! समय हम सबको ललकार रहा है! आने वाला समय हम राजकीय कर्मचारियों व लोक सेवकों के लिए चुनौती भरा है, "जिस दीपक में जान होगी वो ही इन झंझावतों से बचकर प्रकाश कर तिमिर को दूर कर सकेगा"। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) जो अवधारणाओं व सिद्धान्तों तथा सामाजिक सरोकारों के लिए समाज व राष्ट्र के लिए समर्पित होकर संगठनात्मक सुदृढ़ता के साथ आधार लिए है। कहा भी है "संघे शक्ति कलौयुगे" अकेला इन्सान आज के समय व परिपेक्ष्य में मैं समझता हूँ वह असुरक्षित है।

आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एक बार पुनः प्रदेश महासमिति के अधिवेशन के संयोजक सम्मानीय श्यामसुन्दर जी स्वामी, संभाग संगठन मंत्री, सह संयोजक महोदय सम्मानीय विजय कुमार जी, जिलाध्यक्ष संगठन, सीकर, आयोजन स्थल के सी.एल.सी. संस्थान के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री श्रवण जी चौधरी, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय सम्पत सिंह जी, प्रदेश संगठन मंत्री सम्मानीय प्रहलाद जी शर्मा, सभाध्यक्ष महोदय आदरणीय देवलाल जी गोचर, संरक्षक मण्डल में सर्वश्री सम्मानीय नानक जी कुन्दनानी, सन्तोष चन्द्र जी सुराणा, चौथमल जी सनाढ्य, राजनारायण जी शर्मा एवं रामावतार जी शर्मा एवं महामंत्री कार्यालय में मेरा सहयोग करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं, प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य महानुभावों व राजस्थान के कोने–कोने से इस कोरोना महामारी में अपने आपको सुरक्षित कर संगठन के लिए सर्वजन हिताय समर्पित भाव से आहुति देने पधारे प्रदेश महासमिति के सम्मानीय सदस्य महानुभावों, शिक्षक बन्धुओं एवं मातृस्वरूपा बहिनों को महासमिति के अधिवेशन में पदार्पण कर अमूल्य समय का योगदान देने हेतु हार्दिक बधाई देते हुए पुनः आप सभी का हृदय से राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

अरविन्द व्यास
महामंत्री